भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1965
जिसका उत्तर बुधवार 2 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

महाराष्ट्र में भारी उद्योगों की स्थापना

1965. श्री माजीद मेमन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने औद्योगिक विकास हेतु महाराष्ट्र में भारी उद्योगों और लोक उद्यमों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान स्थापित किए गए उद्यमों की संख्या कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): चूंकि, उद्योग राज्य का विषय है, देश के किसी भी भाग में स्थापित भारी उद्योगों से संबंधित कोई भी केन्द्रीकृत आंकड़ा भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा नहीं रखा जाता है। तथापि, भारी उद्योग विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के किसी भी भाग में किसी भी लोक उद्यम की स्थापना नहीं की गई है। भारी उद्योग विभाग की भूमिका इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के प्रशासन तक सीमित है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों ने वाणिज्यिक महत्व पर आधारित अपनी यूनिटों को देश के विभिन्न भागों में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से संपूर्ण देश में उद्योगों की वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर ढांचे में प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराती है। तथापि, कई राज्यों ने उद्योगों के विकास और वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और स्कीम विकसित की हैं और ये राज्य उनकी प्राथमिकताओं और निवेश वातावरण के अनुसार उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देते हैं और इस प्रकृति के ब्यौरे केवल उनके साथ उपलब्ध होने की आशा है।

******